

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र

यह एडिटरियल 22/06/2024 को 'इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली' में प्रकाशित "Rhetoric of Collective Action in North East India" लेख पर आधारित है। इसमें पूर्वोत्तर भारत में सहकारी समितियों की सीमिति प्रभावशीलता की चर्चा की गई है, जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि GIN-FED द्वारा स्वदेशी उत्पादकों को प्रत्यक्षतः सशक्त बनाने के बजाय व्यापारियों पर निर्भर रहा जा रहा है, जहाँ उन स्थानीय सामुदायिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है जो सहयोग के लिये आवश्यक हैं।

प्रलिस के लिये:

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र, मणपुर जैसे हालिया संघर्ष, भारत-म्यांमार-थाईलैंड तरपिकीय राजमार्ग, कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति, काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना, गोल्डन ट्राइंगल, अदरक उत्पादक सहकारी संघ।

मेन्स के लिये:

भारत के लिये पूर्वोत्तर क्षेत्र का महत्त्व, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ।

पूर्वी हिमालय में बसा **भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र** मनमोहक भूदृश्यों, विविध संस्कृतियों और समृद्ध आदवासी वरिासत की भूमि है। हालाँकि, इस क्षेत्र को अपने स्वदेशी समुदायों को मुख्यधारा के विकास आख्यान में पूरी तरह से एकीकृत करने में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

प्राकृतिक संसाधनों और जीवत सांस्कृतिक असमति से संपन्न होने के बावजूद, पूर्वोत्तर भारत कमजोर अवसंरचना, बाज़ारों तक सीमिति पहुँच, सामाजिक असमानताओं और **मणपुर जैसे हालिया संघर्ष** जैसे मुद्दों से जूझ रहा है। इस जटिलता के एक उदाहरण के रूप में असम के कार्बी आंगलों में अदरक की खेती के मामले को देखा जा सकता है, जहाँ एक सहकारी समिति का उद्देश्य स्वदेशी अदरक उत्पादकों को सशक्त बनाना था, लेकिन पारंपरिक संस्थाओं के कमजोर पड़ने और शोषक बच्चौलियों के प्रभुत्व जैसे कारकों के कारण अंततः यह विफल हो गया।

यह मामला इस बात को उजागर करता है कि भारत को अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा देश के शेष भागों के बीच की खाई को दूर करने के लिये और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। **भारत अपने पूर्वोत्तर भूभाग में निवेश कर सांस्कृतिक समृद्धि**, आर्थिक अवसर और पर्यावरण संरक्षण के खजाने का द्वार खोल सकता है।

भारत के लिये पूर्वोत्तर क्षेत्र का क्या महत्त्व है?

- रणनीतिक भू-राजनीतिक अवस्थिति: पूर्वोत्तर को भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाले एक प्रमुख आर्थिक गलियारे के रूप में देखा जाता है।
 - भारत-म्यांमार-थाईलैंड तरपिकीय राजमार्ग और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी अवसंरचना परियोजनाएँ केवल क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य तक सीमिति नहीं हैं, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन के मुकाबले भारत को एक आर्थिक प्रतपिक्ष के रूप में स्थापित करने का भी लक्ष्य रखती हैं।
 - इसकी अनूठी भौगोलिक अवस्थिति इसे **भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति** के लिये महत्त्वपूर्ण बनाती है, जिसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक एवं रणनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करना है।
- समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन: पूर्वोत्तर भारत विश्व के **जैव विविधता संपन्न 'हॉटस्पॉट'** में से एक है, जहाँ वनस्पतियों और जीवों की अनेक दुर्लभ एवं स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
 - उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से लेकर अल्पाइन घास के मैदानों तक इसके विविध पारस्थितिकी तंत्र, पारस्थितिकी संतुलन बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 - इस क्षेत्र में तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले के महत्त्वपूर्ण भंडार भी मौजूद हैं, जो इसे भारत की विकास करती अर्थव्यवस्था के लिये प्राकृतिक संसाधनों का एक मूल्यवान स्रोत बनाते हैं।
- सांस्कृतिक विविधता और जातीय विविधता: पूर्वोत्तर क्षेत्र 220 से अधिक जातीय समूहों और इतनी ही बोलियों के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता का सूक्ष्म रूप में प्रतिनिधित्व करता है।

- संस्कृतियों, परंपराओं और भाषाओं की यह समृद्ध वैश्विक मंच पर भारत की बहुलवादी पहचान और 'सॉफ्ट पॉवर' में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है।
- इस क्षेत्र की अनूठी सांस्कृतिक वरिसत—जिसमें **संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प और पाक-कला परंपराएँ** शामिल हैं, सांस्कृतिक पर्यटन के लिये अपार संभावनाएँ प्रदान करती हैं।
- **कृषि और बागवानी की संभावनाएँ:** पूर्वोत्तर भारत की विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ इसे विभिन्न उच्च मूल्यवान और वदेशी कस्मों सहित कई प्रकार की फसलों की खेती के लिये उपयुक्त बनाती हैं।
 - इस क्षेत्र में **जैविक खेती, पुष्प-कृषि (floriculture) और औषधीय पौधों** की खेती की व्यापक संभावनाएँ मौजूद हैं, जो जैविक और प्राकृतिक उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग के अनुरूप हैं।
- **जल वदियुत उत्पादन:** प्रचुर जल संसाधनों और पहाड़ी इलाकों के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र जलवदियुत उत्पादन की भी अपार क्षमता रखता है।
 - अनुमान है कि इस क्षेत्र में **लगभग 58,000 मेगावाट जल वदियुत क्षमता** है, जो भारत की कुल क्षमता का **लगभग 40%** है।
 - इस क्षमता का दोहन न केवल क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा, बल्कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकेगा।
- **पर्यटन क्षमता:** पूर्वोत्तर भारत के अछूते भूदृश्य, विविध वन्य जीवन, अनूठी सांस्कृतिक वरिसत और 'एडवेंचर टूरिज़्म' के अवसर पर्यटन उद्योग के लिये महत्त्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता प्रस्तुत करते हैं।
 - **काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान** के गैंडा नविस वाले घास के मैदानों से लेकर मेघालय और **केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान** के सजीव रूट ब्रिज (living root bridges) तक, यह क्षेत्र ऐसे अनूठे अनुभव प्रदान करता है जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है।
- **मानव संसाधन विकास:** पूर्वोत्तर भारत में **साक्षरता दर 78.5%** है जो राष्ट्रीय औसत (74%) से उच्च है और यहाँ की युवा आबादी एक जनसांख्यिकीय लाभांश प्रस्तुत करती है, जो भविष्य में भारत के विकास को गति प्रदान कर सकती है।
 - इस भूभाग में शक्तिषा, कौशल विकास और रोज़गार सृजन में निवेश से इस क्षमता का दोहन किया जा सकता है, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र नवाचार एवं उद्यमिता का केंद्र बन सकता है।

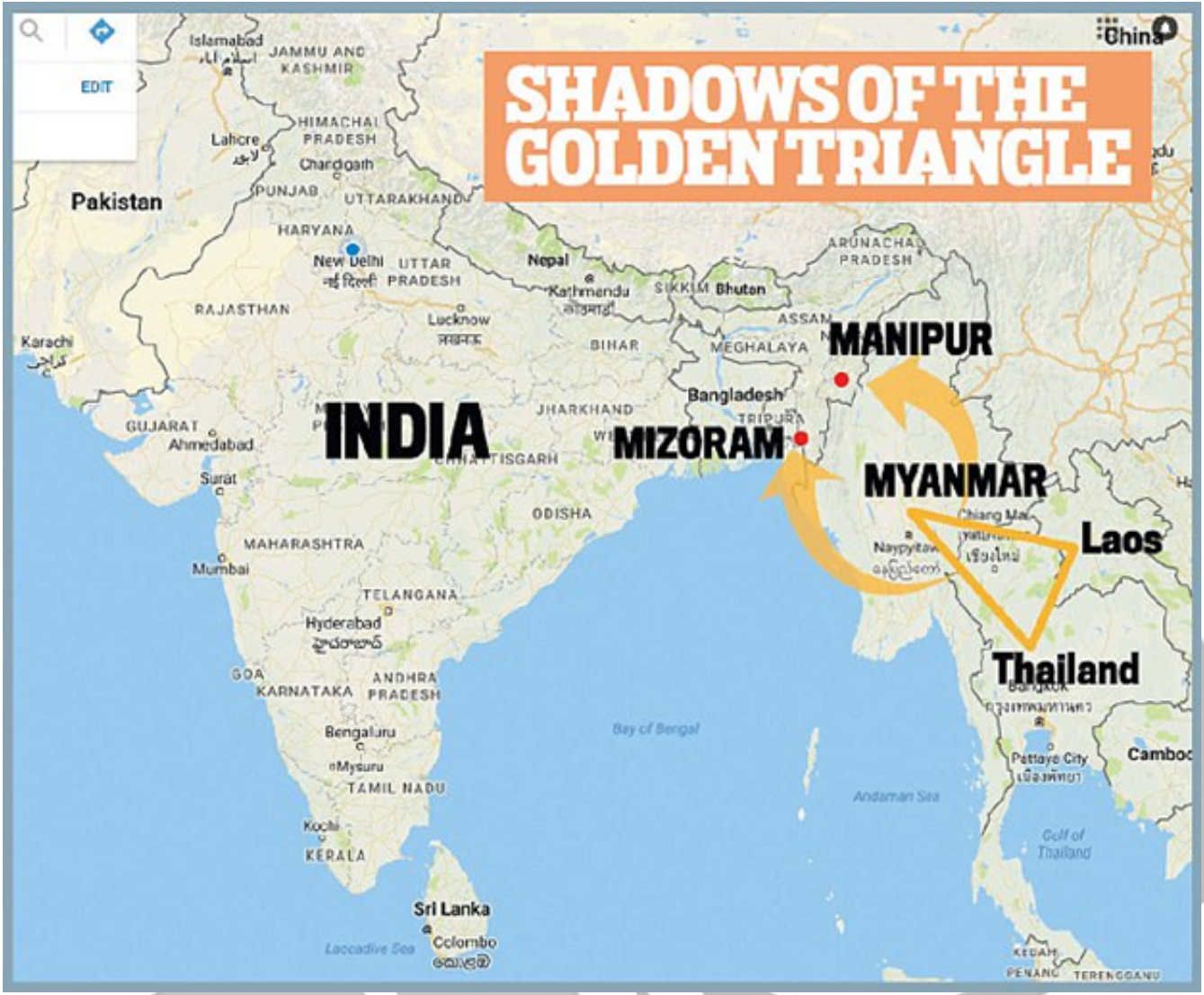
//



भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ:

- **उग्रवाद और जातीय संघर्ष:** कई समूहों के साथ शांति समझौते के बावजूद उग्रवाद की चुनौती बनी हुई है, विशेष रूप से **मणिपुर और नगालैंड** के कुछ हिस्सों में जहाँ वे स्वायत्तता की मांग रखते हैं।
 - **मणिपुर में मैतेई और कुकी जातीय समूहों** के बीच हाल ही में उभरी हिसा (वर्ष 2023) अंतर-जातीय संबंधों की संवेदनशीलता को उजागर करती है।

- ये संघर्ष न केवल सुरक्षा के लिये खतरा पैदा करते हैं, बल्कि विकास संबंधी प्रयासों और वदेशी निवेश में भी बाधा डालते हैं, जिससे फरि अविकास और अशांति का एक ऐसा दुष्चक्र नरिर्मित होता है जिसे तोड़ना कठनि हो जाता है ।
- **कृषि संबंधी चुनौतियाँ:** पूरवोत्तर भारत के कृषि प्रधान अरुथव्यवस्था होने के बावजूद इसे कृषि संबंधी महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है ।
 - सकिकमि ने जैवकि खेती को बढ़ावा दिया, लेकिन इसकी सफलता सीमति रही । **जैवकि उत्पादों के लिये प्रीमियम मूल्यों की कमी, प्रमाणीकरण में कठनिई और सस्ते एवं प्रायः आयातति उरवरकों से प्रतसिपर्द्धा** के कारण कसिान जैवकि खेती को अपनाने में संकोच रखते हैं ।
 - इसके अलावा, बचौलियों का प्रभुत्व पूरवोत्तर कषेतर में कृषि के लिये एक नरिंतर बाधा बना हुआ है । यहाँ तक कि सहकारी समतियों (जैसे अदरक उत्पादक सहकारी संघ) जैसी पहलें भी प्रतसिपर्द्धा के मामले में संघर्षरत रही हैं ।
 - ये बचौलिये प्रायः कसिानों को आवश्यक ऋण और आपूरति पहले ही उपलब्ध करा देते हैं, जिससे ऋण और नरिभरता के एक दुष्चक्र का नरिर्माण हो जाता है ।
 - बाजार पर यह नरियंत्रण बचौलियों को कीमतें तय करने की अनुमतति देता है, जिससे कसिानों को उनके कठोर श्रम के बावजूद नयूनतम लाभ प्रापत होता है ।
- **चीन का बढ़ता प्रभाव और सीमा वविाद:** **अरुणाचल प्रदेश** पर चीन का दावा और सीमा पर उसका अवसंरचना वकिसा गंभीर सुरक्षा चुनौतियों उत्पन्न कर रहा है ।
 - **तवांग (दसिंबर 2022) और डोकलाम कषेतर** में हाल की झड़पें दोनों देशों के बीच के तनाव को रेखांकति करती हैं ।
 - मर्यांमार में चीन के बढ़ते आरुथकि प्रभाव से पूरवोत्तर कषेतर के अलग-थलग पड़ने का खतरा भी पैदा हो गया है, जिससे इस कषेतर में भारत के रणनीतकि हतियों को चुनौती मलि रही है ।
- **जलवायु परविर्तन और पर्यावरणीय कषरण:** पूरवोत्तर कषेतर जलवायु परविर्तन के गंभीर प्रभावों का सामना कर रहा है, जिसमें अनयमति वरुषा, बाढ़ और भूस्खलन शामिल हैं ।
 - वर्ष 2022 में असम में आई बाढ़ इस भेद्यता का एक उदाहरण है जिससे लाखों लोग प्रभावति हुए ।
- **अवसंरचना की कमी और कनेक्टविटि संबंधी समस्याएँ:** 'एक्ट ईस्ट' नीति जैसे हाल के प्रयासों के बावजूद, यह कषेतर अभी भी अवसंरचना के मामले में पछिड़ा हुआ है ।
 - **भारत-मर्यांमार-थाईलैंड त्रपिकषीय राजमार्ग** जैसी प्रमुख परयोजनाओं की धीमी प्रगततिदिकषणि-पूरव एशिया के साथ आरुथकि एकीकरण में बाधा उत्पन्न कर रही है ।
 - कषेतर में लास्ट-मील कनेक्टविटि की स्थिति बिदतर बनी हुई है, जिससे वशिष रूप से दूरदराज के कषेतरों में स्वास्थ्य सेवा, शकिषा और आरुथकि अवसर प्रभावति हो रहे हैं ।
- **आरुथकि अवकिसा और बेरोज़गारी:** इस कषेतर की अरुथव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारति है और कषेतर का सीमति औद्योगिकीकरण ही हुआ है ।
 - **पूरवोत्तर औद्योगिक वकिसा योजना (2017)** जैसी हालिया पहलों को नविश आकर्षति करने में सीमति सफलता प्रापत हुई है ।
 - युवाओं में उच्च बेरोज़गारी सामाजकि अशांति और पलायन को बढ़ावा देती है, जिससे प्रतभि पलायन या 'बरेन डरेन' की स्थिति बिनती है जो वकिसा को और अधकि बाधति करती है ।
- **मादक पदार्थों की तसकरी और सीमा पार अपराध:** 'गोलडन ट्राइंगल' से पूरवोत्तर कषेतर की नकिटता ने इसे मादक पदार्थों की तसकरी के प्रतसिंवेदनशील बना दिया है ।
 - हाल के वर्षों में मादक पदार्थों की जबती में, वशिष रूप से **मणापुरि और मज़ोरम** में, वृद्धि देखी गई है ।
 - इससे न केवल कानून परवर्तन संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, बल्कि युवाओं में **नशे की लत जैसे सामाजकि संकट** भी उत्पन्न होते हैं, जिससे कषेतर की स्वास्थ्य सेवा और सामाजकि ताने-बाने पर प्रतकिूल प्रभाव पड़ता है ।



- **राजनीतिक अस्थिरता और शासन संबंधी मुद्दे:** सरकार में बार-बार होने वाले परिवर्तन, वशिषकर मणपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में, नीतगित नरिंतरता में बाधा डालते हैं।
 - **जातीय राजनीति, स्वायत्तता की मांग और राष्ट्रीय राजनीतिक गतशीलता** की जटलि अंतरक्रिया के परिणामस्वरूप प्रायः अस्थिर गठबंधनों का निर्माण होता है।
 - **नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)** पर हाल के विवादों ने राजनीतिक परिदृश्य को और अधिक जटलि बना दिया है, जिससे विरोध प्रदर्शन और अंतर-सामुदायिक तनाव बढ़ गया है।

भारत पूर्वोत्तर क्षेत्र के एकीकरण को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकता है?

- **‘उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम’** सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम: भारत के उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी राज्यों के बीच वृहतस्तरीय एवं दीर्घकालिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम शुरू किया जाए।
 - इसमें वर्षावधिक छात्र आदान-प्रदान, आर्टसिट रेसीडेंसी और बजिनेस इनक्युबेशन कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं।
 - इसका लक्ष्य भौगोलिक दृष्टि से दूर अवस्थित इन क्षेत्रों के बीच गहन, व्यक्तिगत संबंध का सृजन करना और ज़मीनी स्तर पर समझ एवं एकीकरण को बढ़ावा देना होगा।
- **‘डिजिटल सलिक रोड’ पहल:** पूर्वोत्तर भारत के लिये विशेष रूप से एक अत्याधुनिक डिजिटल अवसंरचना नेटवर्क विकसित किया जाए, ताकि इसे भारत के डिजिटल नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके।
 - इसमें टेक कंपनियों के लिये कर प्रोत्साहन, **वशिषिट डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों** के लिये उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए ‘सलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट’ की स्थापना करना शामिल हो सकता है।
 - इससे न केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र **भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में एकीकृत** होगा, बल्कि म्यांमार, वियतनाम आदि दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी स्थानांतरित करने के माध्यम से इसे अग्रणी क्षेत्र भी बना देगा।
- **अंतरराष्ट्रीय स्वदेशी ज्ञान विश्वविद्यालय:** स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूर्वोत्तर भारत में एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, जिसमें भारत के अन्य भागों और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से विद्वानों एवं छात्रों को आमंत्रित किया जाए।
 - यह संस्थान स्वदेशी संस्कृतियों, पारंपरिक चिकित्सा, सतत् कृषि और पारिस्थितिक संरक्षण के अध्ययन एवं संरक्षण के लिये एक वैश्विक केंद्र बन सकता है, जो पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक सांस्कृतिक एवं बौद्धिक सेतु के रूप में स्थापित कर

सकता है।

- **पूर्वोत्तर ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र:** खेलों के प्रति पूर्वोत्तर क्षेत्र के जूनन का लाभ उठाते हुए यहाँ एक अत्याधुनिक ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाए।
 - यह वभिन्न ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिये भारत का प्राथमिक प्रतिष्ठान बन सकता है, जिससे इस क्षेत्र की ओर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित होगा और खेलों के माध्यम से गौरव एवं एकीकरण की भावना को बढ़ावा मिलेगा।
- **फ्लोटिंग मार्केट टूरजिजम सर्कट:** दक्षिण-पूर्व एशियाई मॉडल से प्रेरणा लेते हुए अनूठी भारतीय विशेषता के साथ पूर्वोत्तर भारत की नदियों में तैरते बाजार या फ्लोटिंग मार्केट का एक नेटवर्क विकसित किया जाए।
 - यह एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन सकता है, जो क्षेत्र की विविधता को प्रदर्शित करेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और भारत के पर्यटन पर्यटन में एक विशिष्ट पूर्वोत्तर ब्रांड का निर्माण करेगा।
 - **बाँस क्रांति कार्यक्रम:** पूर्वोत्तर में बाँस की खेती और उत्पाद विकास पर केंद्रित एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाए।
- इसमें बाँस से बने वस्त्रों से लेकर निर्माण सामग्री और जैव ईंधन तक सब कुछ शामिल किया जा सकता है।
 - पूर्वोत्तर भारत को एक संवहनीय **'बाँस अर्थव्यवस्था' (Bamboo Economy)** का केंद्र बनाने से आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है और इस क्षेत्र को पर्यावरण-अनुकूल नवाचार में अग्रणी बनाया जा सकता है।
- **हिमालयी औषधीय अनुसंधान गलियारा (Himalayan Medicinal Research Corridor):** पारंपरिक हिमालयी चिकित्सा (पूर्वोत्तर के ज्ञान को आयुर्वेद एवं आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करते हुए) के लिये एक विशेष अनुसंधान एवं विकास गलियारे का निर्माण किया जाए।
 - इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र वैकल्पिक चिकित्सा अनुसंधान एवं उत्पादन में वैश्विक अग्रणी क्षेत्र के रूप में स्थापित हो सकता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और मुख्यधारा भारत के साथ इसका वैज्ञानिक एकीकरण हो सकेगा।
- **स्वायत्त वाहन परीक्षण स्थल:** चुनौतीपूर्ण इलाकों में स्वायत्त वाहनों के परीक्षण के लिये पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों को परीक्षण क्षेत्र के रूप में नामित किया जाए। पूर्वोत्तर भारत का अनूठा भूदृश्य वैश्विक ऑटो एवं टेक कंपनियों को आकर्षित कर सकता है, जिससे यह क्षेत्र परिवहन प्रौद्योगिकी के भविष्य में एकीकृत हो सकता है।

अभ्यास प्रश्न: पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास एवं कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये आवश्यक चुनौतियों और रणनीतिक पहलों की चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. नमिनलखिति युगमों पर वचिार कीजयि: (2013)

जनजाति	राज्य
1. लमिबू	सक्किमि
2. कार्बी	हमिचल प्रदेश
3. डोंगरिया कोंध	ओडिशा
4. बोंडा	तमलिनाडु

उपर्युक्त युगमों में से कौन-से सही सुमेलति हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (A)